

like to know whether the Government proposes to stop the mushroom growth of cabaret culture.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: of cabaret culture.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: This whole problem is an extremely serious one and unless and until the socio-economic problems are solved, we will continue to be plagued by it. May I know from the hon. Minister what the Government is doing about taking steps to rehabilitate the women who are misled and who fall victims to this totally immoral and anti-social traffic? What does Government purpose to do about seeing that such rehabilitated people are absorbed into the employment force and into the society in our country?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I fully agree with the Hon. Member that the bulk of the problem depends on the socio-economic matter and unless there is general socio-economic improvement in the country, it is almost impossible to tackle this serious problem. However, as I have pointed out, in the new provisions of the amended Act we have mentioned about protective homes and corrective institutions. There, these people will be rehabilitated and there will also be probation for them as the Probation of Offenders Act has been made applicable to these cases. Apart from these, some of the unfortunately girls may volunteer to take advantage of the new provisions, so that they may be taken away from the brothels and may see better life.

श्री श्रीमती प्रवेशा ल्योणी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जब किसी वेश्यालय में कोई प्रोस्टीट्यूट और ऑफेंडर पकड़े जाते हैं तो बेचारी लड़की को ही दण्डनीय माना जाता है और जो ऑफेंडर होता है, उसे दण्डनीय नहीं माना जाता है? क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का कोई संशोधन संविधान में करेंगे कि जो व्यक्ति वेश्यालय में जाता है वह भी दण्डनीय हो?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The Act does not prohibit prostitution, but it applies to control commercialised prostitution, so that they may not live on prostitution.

The Law Commission has advised that it will not be proper to punish the man because the initial offence is not a criminal offence. Therefore, there is no question of abetment in this offence.

राजस्थान में कीड़ों से फसल की
नुकसान
+

* 311. श्री होलत राम सारन :
श्री जगदीश प्रसाद साधु :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान में पिछले दो तीन वर्षों से कातरा, एक प्रकार का श्वेत कीड़ा, तथा चेपा से खरीफ की फसल खराब हो रही है; जिस के कारण किसानों को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फसल को बचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Pests like white grub, katra (red-hairy caterpillar) and chepa (aphids) have been affecting the Kharif crops in Rajasthan for the last two, three years in varying degrees. However, as a result of measures like chemical treatment of the affected area, use of light traps, mechanical control, etc., it has been possible to avert serious damage to the crops.

श्री होलत राम सारन : मैंने उपचार ले लिए हैं, लेकिन मैंने पूछा था कि क्या वहाँ यह उपचार क्रिये नहीं या उपलब्ध नहीं हुए?

इस से राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के किसानों को फसल नष्ट होती आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन कीड़ों और बीमारियों के कारण इन वर्षों में कितने क्षेत्र का फसल नष्ट हुई और उस से कितने किसानों को हानि हुई? कितने किसान इस से प्रभावित हुए?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह तो ठीक पता नहीं है कि कितने किसानों को नुकसान हुआ है या कितने किसानों के खेतों में यह पड़ेंगे, लेकिन ऐसी इत्सिला स्टेट गवर्नमेंट से मित्रों है कि इस खतरे का प्रसर 13 लाख, 27 हजार 896 हेक्टर जमीन पर हुआ है। उसमें से 3 लाख 66 हजार 712 हेक्टर को मैकेनिकल ट्रीटमेंट से बचाया है और 14 हजार 569 हेक्टर को कॅमिकल कंट्रोल से बचाया है, और दवाएं जो इस्तेमाल की गई हैं, उन की डिटल भी मेरे पास मौजूद है।

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मंत्री महोदय द्वारा जवाब देते हैं। आप मंत्री जी से कहिये कि वह सवाल का पूरा जवाब दें कि कितने किसानों को नुकसान हुआ है? ये लोग क्या काम करते हैं, सवाल का जवाब देने के लिये पूरा पता क्यों नहीं करते हैं? इन को पता लगा कर रखना चाहिये या कि कितने किसानों को नुकसान पहुंचा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को प्राटेंशन मन दीजिये, किसानों का जब भी सवाल आता है, मंत्री लोग टल देते हैं।

श्री बीसत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में यह निहित है कि कितने क्षेत्र में कितनी फसल की हानि हुई है और इस से कितने किसान प्रभावित हुए हैं। मंत्री महोदय को यह माँसूम करना चाहिये था। मुझे खेद है कि मैंने जो सूचना चाही, वह मंत्री महोदय

द्वारा नहीं दी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि इस प्रकार के कीड़ों, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोप से किसानों की बहुत बड़े क्षेत्र की फसल नष्ट होती रहती है, मगर उस से किसानों को सुरक्षा और संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने जो इनफार्मेशन दी है, वह मैंने दी है कि इतनी फसल को नुकसान हुआ है और इतनी फसल पर कटरा ने हमला किया। अगर माननीय सदस्य व्हाइट प्रब के बारे में फेक्ट चाहते हैं तो व्हाइट प्रब से जयपुर, राजस्थान में सोलह हजार हेक्टेयर एरिया में 1970 में नुकसान हुआ, जिसको मैकेनिकल ट्रीटमेंट और कॅमिकल ट्रीटमेंट से बाबू में लाने की कोशिश की गई। उनका वहना रही है कि बहुत से एरिया को हर साल इस तरह से पेस्ट्स से नुकसान होता रहता है। लेकिन उस के इलाज के लिये वे दोतीन तरीके अपनाये जाते हैं, जिन के बारे में मैंने इनफार्मेशन दी है। कॅमिकल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन उस के बावजूद थोड़ा बहुत नुकसान होता है।

श्री बीसत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने दोतीन साल पहले के बारे में पूछा है, लेकिन मंत्री महोदय ने वह सूचना नहीं दी है। फसल नष्ट हो जाती है, मगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। उन के लिये बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है।

MR. SPEAKER: You have put two questions.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI: For the last two or three years, the farmers have been incurring great loss, not in 1970.

you for any supplementary.

MR. SPEAKER: I have not called

श्री बालू कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा गया है दो-तीन साल पहले का। जबकि मंत्री महोदय ने 1970 के बारे में बताया है। 1970 के बारे में किस ने पूछा है ?

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि पिछले दो-तीन साल में ग्राइंट ग्रब में कितनी हार्नि हुई है। मंत्री महोदय ने 1970 के बारे में बत या है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने 1970 के बारे में जवाब नहीं दिया है। मैंने 1977-78 के बारे में इस साल के, 1978 के खरीफ के बारे में बताया है।

श्री धीरू बलवीर सिंह : क्या इस बीमारी को रोकथाम न होने की वजह यह है कि कीड़ों को इन्फेक्टाइड की इम्युनिटी हां गई है ? क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी, जिस के जरिये इस बीमारी को रोक जा सके और इन दव इयों की इम्युनिटी न हो सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसा तो नहीं है कि उन्हें इम्युनिटी हां गई है। जहां दवाई इस्तेमाल हाती है, वहां कीड़े मर भी जाते हैं। लेकिन हर जगह दवाई इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। उन को कंट्रोल करने के लिये और तरोंके इस्तेमाल किये जाते हैं। ल इट ट्रेप, कैमिकल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल इस्तेमाल किया जात है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Models of Rural Development Scheme

*306. SHRI A. BALA PAJANOR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing:

(a) whether under the scheme of Rural Development which has been in force for some time, any worthwhile models have been developed for application on an all India scale;

(b) if so, the essential features of the models and the Centres at which such models have been structured; and

(c) the extent to which local skills and local resources have been suitably integrated in such models?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Three special rural development programmes namely, Small Farmers Development Agency, Drought Prone Areas Programme and the Command Area Development Programme have been in operation for quite some time. These programmes were initiated to achieve specific objectives in certain specified areas in the country. The Small and marginal farmers schemes were introduced during the Fourth Plan for making the small and marginal farmers economically viable and for improving the lot of landless agricultural labourers by raising the output of small holdings and generating employment through subsidiary occupations. The programme basically follows a beneficiary oriented approach.

A programme for providing development investments in areas where drought had been a recurring feature was re-oriented as an area development programme under the name Drought Prone Area Programme in the Fifth Plan. The basic objective of the programme is to eliminate or reduce considerably the incidence of drought and scarcity in the vulnerable areas over a period of time and also to help the small and marginal farmers and landless agricultural labourers in raising their income levels. Though the D.P.A.P. follows essentially an area development approach, the individual beneficiary approach similar to that of S.F.D.A. has also been adopted under the programme.

The Command Area Development Scheme was introduced in the Central Sector in 1974 with a view to bringing about faster and optimum utilisation